DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
NEW DELHI | THURSDAY, 29 JUNE, 2023

DATED

3 landfill sites to be cleared in 18 mths: L-G

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: Delhi Lt Governor V K Saxena on Wednesday assured that the three landfill sites in the national Capital will be cleared in the "next 18 months" while the Najafgarh drain will be cleaned in the "next few months".

Speaking at an event here on 'Delhi 2041 - New Master Plan', Saxena cited various initiatives undertaken in the development of Yamuna flood plains, revamping of roads, and removal of garbage dumps in the city, under his tenure in the last year.

He called upon Delhi citizens to participate in the beautification and grooming of the city.

The Delhi Development Authority (DDA) issued a statement after the event which was also attended by Subhasish Panda, vice chairman of the authority, who said the Master Plan of Delhi 2041 (MPD-2041) would ensure sustainable development and will be notified soon.

Highlighting the cleanliness work done in the national Capital at an "unprecedented pace", Saxena assured that the three "garbage mountains" will be cleared in the next 18 months, and the Najafgarh Drain, spread over 57 km, will also be completely cleaned very soon.

"Out of the 57-km stretch of the Najafgarh Drain, 30 km of it has been cleaned and the rest will be cleaned in the next few months," he was quoted as saying in the statement.

The interactive session on MPD-2041 was organised by the PHD Chamber of Commerce and Industry (PHDCCI).

Flattening of garbage dumps at Okhla, Bhalswa, and Ghazipur was being done on a "war footing", the PHDCCI said in another statement.

He emphasised that coordination among departments can help achieve the targets, saying that public participation can accomplish a lot of things.

The L-G said inclusivity lay at the heart of the this Master Plan.

Drafting of the Master Plan, which is almost ready, meticulously took into account the importance of providing equal opportunities to all segments of society, by ensuring equitable access to resources, services, and economic opportunities, Saxena said.

The plan aims to foster inclusive growth and prosperity. Entrepreneurship, innovation, and job creation will be nurtured, contributing to the overall economic development of the city, the L-G added.

He also said that like never before, this year thousands of residents of Delhi performed yoga at eight locations on the occasion of the International Day of Yoga, along the cleaned stretch of the Najafgarh Drain.

The L-G asked citizens of Delhi to remain vigilant and raise their voices for better roads, other basic facilities, and also against encroachment.

"People have the right to ask for a clean environment," he said.

On an emotional note, he stressed that it is our duty to bring back the lost glory of the Yamuna river for future generations. He said in the endeavour, an 11 km patch of Yamuna from Signature Bridge to the ITO Barrage has been cleaned.

Talking about employment generation in the national capital, he said in the last year, 17,000 permanent jobs have been provided and 26,000 people have been trained in skill development.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

amarujala.com

NAME OF NEWSPAPERS बृहस्पतिवार, 29 जून 2023 DATED

डीडीए अफसरों को भेजे एलजी के नाम से मैसेज, प्राथमिकी दर्ज

आरोपी के मैसेज भेजने का उद्देश्य अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के नाम से दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अधिकारियों को मैसेज भेजने का मामला सामने आया है। आरोपी ने मैसेज में न तो कोई जानकारी मांगी और न ही कोई अन्य बात की। ऐसे में आरोपी के मैसेज भेजने का उद्देश्य अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है।

दक्षिण जिले की साइबर थाना पुलिस ने डीडीए के अधिकारियों की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दक्षिण जिला पुलिस अधिकारियों का कहना है कि व्हाट्सएप की ओर से का कोई जवाब नहीं दिया है। दिल्ली पुलिस व्हाटसएप को तीन रिमाइंडर भी भेज चुकी है।

दक्षिण जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी ने उपराज्यपाल का फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बना रखा था। उसने व्हाट्सएप पर उपराज्यपाल की फोटो डीपी में लगा रखी थी। आरोपी जालसाज ने 23 जून को डीडीए के वरिष्ठ अधिकारी को मैसेज भेजे। उसने मैसेज में लिखा कि हैलो, कैसे हो और अभी इस समय कहां हो। इसके बाद उसने मैसेज भेजा कि वह उपराज्यपाल श्री वीके सक्सेना बोल रहा है। आरोपी ने तीन से चार मैसेज भेजे। इसके बाद उसने दो से तीन व्हाट्सएप कॉल की। जालसाज ने जब मैसेज में श्री लिखा तो उससे अधिकारियों को संदेह हो गया। इसके बाद डीडीए के सतर्कता विभाग की ओर से दक्षिण जिला पुलिस को शिकायत दी गई। साइबर थाना पुलिस ने 25 मई को एफआईआर दर्ज की। साइबर थाना प्रभारी अरुण कुमार वर्मा की देखरेख में इंस्पेक्टर हंसाराम मामले की जांच कर रहे हैं।

मास्टर प्लान-2041 का प्रारूप तैयार: एलजी

नई दिल्ली। मास्टर प्लान-2041 का प्रारूप लगभग तैयार हो चुका है। इसमें समाज के सभी वर्गों को सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। यह जानकारी उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बुधवार को पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स की बैठक में दी। इस मौके पर उपराज्यपाल ने कहा कि मास्टर प्लान विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने वाला है। इसके माध्यम से रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जाएगा। दरअसल मास्टर प्लान को तैयार करने के दौरान दिल्ली के बुनियादी ढांचे के विकास पर फोकस रखा गया है। इसके अलावा दिल्ली की जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए प्रावधान किए है। मास्टर प्लान को तैयारी करने के दौरान परिवहन, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर ध्यान दिया है। ब्यूरो

उपराज्यपाल ने द्वारका क्रेच में छह पद किए स्वीकृत

नई दिल्ली। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने द्वारका कोर्ट कॉम्पलेक्स स्थित क्रेच संचालन को लेकर खाली पड़े छह पदों को स्वीकृति दे दी है। इसमें एक पद क्रेच प्रभारी, दो कर्मचारी, दो हेल्पर व एक सुरक्षाकर्मी का है। इस क्रेच में 30 बच्चे रहे हैं, जिसमें 12 बच्चे तीन वर्ष व उससे कम आयु के हैं और 18 बच्चे तीन वर्ष की आयु से ऊपर के हैं। नियम अनुसार पांच बच्चे होने पर क्रेच को सभी सुविधाएं देनी होती है। ब्यूरो

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

29 जून • 2023 राष्ट्रीय सहारा
NEWSPAPERS------ DATED------

खुद को एलजी बताने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर

- **एक व्यक्ति ने 23 मई को 'व्हाट्सऐप' पर डीडीए के दो अधिकारियों से संपर्क किया था**
- **उस व्यक्ति का इरादा डीडीए अधिकारियों को डराना और किसी न किसी बहाने से पैसे की मांग करना था**

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ ने खुद को दिल्ली का उपराज्यपाल (एलजी) वी. के. सक्सेना बताने के आरोप में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के सतर्कता विभाग द्वारा दर्ज की गई एक शिकायत के आधार पर 25 मई को प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक व्यक्ति ने 23 मई को 'व्हाट्सएप' पर उसके दो अधिकारियों से संपर्क किया था।

प्राथमिकी के अनुसार, सतर्कता विभाग के दो अधिकारियों को पहले एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप पर फोन आया और फोन करने वाले ने खुद को उपराज्यपाल सक्सेना बताया। यह सुनकर अधिकारी हैरान रह गए और फोन काट दिया। फोन करने वाले ने व्हाट्सएप पर सक्सेना की तस्वीर (डिस्प्ले पिक्चर में) लगा रखी थी। आरोपी ने दोनों अधिकारियों को संदेश भी भेजे जिसमें लिखा था, 'हाय, मैं दिल्ली का एलजी विनय कुमार सक्सेना हूं।' मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने कहा, ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति का इरादा इन अधिकारियों को डराना और किसी न किसी बहाने से पैसे की मांग करना था, लेकिन अधिकारी सतर्क थे और उसके झांसे में नहीं आए। उन्होंने तुरंत अपने वरिष्ठों को मामले की सूचना दी और विभाग को भी सतर्क किया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें जालसाजों ने इस तरीके का इस्तेमाल कर लोगों को ठगा है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
& CLIPPING SERVICE

the pioneer
NEW DELHI | THURSDAY | JUNE 29, 2023

Inclusivity lies at heart of Delhi 2041 Master Plan: LG Saxena

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

Delhi Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena on Wednesday said here inclusivity lay at the heart of the Delhi 2041 Master Plan adding its draft is almost ready taking into account the importance of providing equal opportunities to all segments of society by ensuring equitable access to resources, services, and economic opportunities.

Addressing an interactive session organized by the PHD Chamber of Commerce on the theme, Delhi 2041 – New Master Plan, he also said the plan aims to foster inclusive growth and prosperity. Entrepreneurship, innovation, and job creation will be nurtured, contributing to the overall economic development of the city, Saxena said.

To achieve this, infrastructure development is one of the key focus areas of the plan and has tried to take into account the population growth trends and projected economic trajectory over the next 20 years, he said.

Saxena identified five key areas around which the Master Plan has shaped its provisions. They include Efficient Transport Systems,

Affordable Housing, Healthcare Facilities, Educational Institutions and Digital Connectivity.

Preservation of the City's rich heritage, revitalizing our urban areas, vide Green as well as Brown Field development and connectivity and mobility that essentially take into consideration environmental sustainability are other equally prominent aspects of plan, he said. Saxena took the opportunity to also underline his experience during the last one year as the Lt. Governor. Highlighting the key areas that he had tried to address, Saxena said focus was on permanent employment in government to end contractual ad hocism and favouritism. Over 15,000 permanent appointments in Delhi Government were made during the last one year.

Moreover, 26,000 individuals were provided with skilled development / upskilling training in different vocations like electronics, plumbing, carpentry, wellness etc. by NDMC

Rejuvenation of Yamuna, as mandated by the NGT through the HLC was taken in the right earnest. Other focus areas were

Restoration of Yamuna floodplains.Cleaning of sewer drains, not carried out for the last 10 years and clogged up to 90% started - 40 kms of the 200 kms were completed.

Innovative means of improving the water quality by way of natural treatment through plants and oxidation was undertaken, he said. Revamp of Roads and arterial stretches was carried out, Saxena said

Cyber Cell registers FIR against unknown man for impersonating LG

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

The Delhi Police's Cyber Cell has registered an FIR against an unidentified person for allegedly posing as Delhi Lieutenant Governor V K Saxena, officials said.

The FIR was filed on May 25 on the basis of a complaint lodged by the Delhi Development Authority's (DDA) Vigilance Department alleging that the fraudster contacted two of its officers on WhatsApp on May 23.

According to the FIR, the two vigilance officers first received WhatsApp calls from an unknown number and the caller introduced himself as Saxena.

The officers were surprised to hear this and disconnected the calls.

The caller had also put a picture of the LG as his display picture (DP). The accused also sent text messages to the two officers that read, "Hi, I am Delhi LG Vinai Kumar Saxena."

पंजाब केसरी 29 जून, 2023
DELHI

मंजूरी लेकर ही भूमि का अधिग्रहण करें अधिकारी : पीडब्ल्यूडी

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : लोक निर्माण विभाग ने अधिकारियों को भूमि कब्जे की प्रक्रिया पूरी होने और स्थानीय निकाय की मंजूरी लेने के बाद ही परियोजनाएं आवंटित करने का निर्देश दिया है। 27 जून को जारी एक सकुर्लर में विभाग ने कहा कि इससे उन विवादों से बचने में मदद मिलेगी, जिनके परिणामस्वरूप मध्यस्थता होती है। सकुर्लर में कहा गया है कि यह देखा गया है कि बाधा-मुक्त भूमि की उपलब्धता और स्थानीय निकाय की मंजूरी के बिना ही काम दे दिया जाता है। इसके कारण, ठेकेदारों के साथ विवाद उत्पन्न होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप मध्यस्थता और अन्य जटिलताएं होती हैं। इसमें कहा गया है कि कभी-कभी, साइट/भूमि की अनुपलब्धता और एमसीडी, डीयूएसी, डीडीए, डीपीसीसी और डीएफएस जैसे नियामक निकायों की मंजूरी न मिलने के कारण काम शुरू हुए बिना ही अनुबंधों को रद्द करना पड़ता है। सकुर्लर में सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल 2022 में एक प्रावधान का हवाला दिया गया है जो एनआईटी के अनुमोदन से पहले आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है जिसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। प्रावधान के अनुसार स्थल/भूमि की उपलब्धता एवं अन्य स्वीकृतियां आवश्यक हैं। इसमें कहा गया है कि इसलिए, यह निर्देशित किया जाता है कि काम सौंपने से पहले बाधा मुक्त भूमि की उपलब्धता और स्थानीय निकायों की मंजूरी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

डीडीए की आवासीय योजना का चौथा चरण 30 से

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : डीडीए यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण अपनी आवासीय योजना का चौथा चरण 30 जून से शुरू करने जा रहा है। इसमें डीडीए की तरफ से कुल 5,540 फ्लैटों की नीलामी की जाएगी। पहले आओ, पहले पाओ की तर्ज पर शुरू की जाने वाली बुकिंग प्रक्रिया में लोगों को लोक नायक पुरम, रोहिणी, सिरसपुर और नरेला में कुल 4400 एलआईजी (लो इनकम ग्रुप) फ्लैट, नरेला में 900 ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) फ्लैट, द्वारका और नरेला में 200 एमआईजी (मिडल इनकम ग्रुप) फ्लैट और जसोला में 40 एचआईजी (हाई इनकम ग्रुप) फ्लैट के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का अवसर मिलेगा। डीडीए के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार लोगों के लिए 30 जून को डीडीए की वेबसाइट में 12 बजे से पहले आओ पहले पाओ की डीडीए की आवासीय योजना के मद्देनजर रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया जाएगा।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

the pioneer
NEW DELHI | FRIDAY | JUNE 30, 2023

DISCOM inspecting, maintaining electrical lines in public places

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

As a part of a pre-monsoon safety drive, DISCOM is conducting inspections and maintenance of electrical equipment and lines installed in public areas to minimise the risk of electricity-related incidents.

The drive aimed to ensure the safety of DISCOM consumers was carried out in view of the two deaths due to electrocution in Delhi within a span of 48 hours. As a part of the ongoing preventive maintenance activity, the DISCOM is conducting tree trimming exercises in the vicinity of electrical installations, poles, and overhead lines to prevent leakage current and power interruption, it said.

According to the statement, DISCOM has recently conducted leakage testing of 9,154 poles, 300 PWD/MCD poles, 66 ATMs, and 81 streetlight poles installed in MCD and DDA parks, and the same drive shall be continued. Due attention is being given to ensuring the healthiness of the earthing of electrical installations.

"The DISCOM has also carried out safety audits of more than 1,100 major public installations like malls, hospitals, schools, and colleges to ensure public safety and will continue to do so throughout the year," it said.

amarujala.com
शुक्रवार, 30 जून 2023

डीडीए के 5540 फ्लैटों के लिए पंजीकरण आज से

नई दिल्ली। राजधानी में मकान नहीं मिलने से परेशान लोग शुक्रवार से डीडीए की पहले आओ, पहले पाओ आवासीय योजना के तहत आवेदन कर सकते है। डीडीए ने बीते दिनों इस योजना को स्वीकृति दी थी। योजना के तहत शुक्रवार से ऑनलाइन आवेदन किए जा जा सकेंगे।

डीडीए के 5540 फ्लैटों के लिए 10 जुलाई तक आवेदन कर सकते है। डीडीए ने योजना में जमोला के 40 एचआईजी, द्वारका और नरेला के 200-200 एमआईजी, नरेला के 900 ईडब्ल्यूएस, लोक नायक पुरम, रोहिणी, सिरसपुर और नरेला के 4400 एलआईजी फ्लैट शामिल किए है। डीडीए ने जमोला के एचआईजी फ्लैटों की कीमत 2.08 से 2.18 करोड़, नरेला के एमआईजी फ्लैटों की कीमत एक करोड़, द्वारका के एमआईजी फ्लैटों की कीमत 1.25 से 1.35 करोड़, नरेला और रोहिणी में एलआईजी फ्लैटों की कीमत 15 लाख रुपये, सिरसपुर में एलआईजी फ्लैटों की कीमत 17 लाख, लोक नायक पुरम में एलआईजी फ्लैटों की कीमत 30 लाख, नरेला के ईडब्ल्यूएस फ्लैटों की कीमत 10 से 13 लाख तय की है। बुकिंग के लिए डीडीए की साइट http://www.dda.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस साइट पर एक लिंक उपलब्ध होगा और उस पर क्लिक करना। ब्यूरो

दैनिक भास्कर
नई दिल्ली, शुक्रवार 30 जून, 2023

करंट से 48 घंटे में दो मौतों के बाद डिस्कॉम ने शुरू किया सुरक्षा अभियान

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

डिस्कॉम बिजली संबंधित दुर्घटना के जोखिम कम करने को सार्वजनिक क्षेत्रों में स्थापित उपकरणों और लाइनों का निरीक्षण-रखरखाव कर रहा है। 48 घंटे में करंट से हुई दो मौतों के बाद डिस्कॉम उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अभियान चला रहा है। डिस्कॉम ने हाल ही में एमसीडी और डीडीए पार्कों में स्थापित 9154 खंभों, 300 पीडब्ल्यूडी/एमसीडी खंभों, 66 एटीएम और 81 स्ट्रीटलाइट खंभों से करंट रिसाव परीक्षण किया है। मॉल, अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजों जैसे 1,100 से अधिक प्रतिष्ठानों का सुरक्षा ऑडिट किया है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-- THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI * THURSDAY, JUNE 29, 2023 ----------DATED----------

Industry body seeks early notification of 2041 master plan

Vibha.Sharma@timesgroup.com

New Delhi: Raising concern over increasing illegal construction on agricultural land, members of PHD Chamber of Commerce and Industry (PHDCCI) on Wednesday requested lieutenant governor and Delhi Development chairman VK Saxena for early notification of Master Plan of Delhi-2041. The commerce body had organised an interactive session on the master plan wherein Saxena and DDA vice-chairman Subhasish Panda were present.

The session started with the chair, PHDCCI's Delhi-NCR unit, Mukesh Gupta, raising concerns over colonies coming up on agricultural land illegally. "While the master plan was prepared after several studies and deliberations, it has not been implemented so far. We expect that the problem of illegal colonies on agricultural land will be addressed as soon as the plan comes into force," he said.

Pradeep Multani, former president of PHDCCI, stated that "the master plan is eyeing equitable and sustainable development of Delhi". "It also includes policies for green development areas and land pooling. While both the policies are crucial for achieving the concept of sustainable development and supporting urban farmers, these are stuck for years. If the delay continues, then it would lead to a trust deficit among stakeholders," he said.

Replying to the members' queries, the DDA vice-chairman said that the land pooling policy came in 2013, followed by an amendment in 2018. "While some amendments in the DDA Act are awaited, we have already found success in getting 70% contiguous land in two sectors where consortiums have been formed and landowners can pursue developers for development purposes. We will facilitate them in all possible manner," said Panda.

The upcoming master plan aims to foster inclusive growth and prosperity, said the LG. "To achieve this, infrastructure development is one of the key focus areas of MPD 2041, which has tried to take into account the population growth trends and projected economic trajectory over the next 20 years," Saxena stated.

The LG further claimed that the three garbage mountains would be cleared in the next 18 months and the Najafgarh drain, spread over 57 km, would also be completely cleaned very soon. He stated that about 11 km of the Yamuna from Signature Bridge to ITO barrage had been cleaned and work was in progress at other places.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- । नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । गुरुवार, 29 जून 2023 -D

मलबा डालने पर चालान काट रहे, वसूलने में फेल

616 चालान, एक की भी वसूली नहीं

साल	चालान	कितने के	रिकवरी
2018	1	50,000	शून्य
2019	186	90,40,000	22,92,500
2020	54	21,30,000	5,95,000
2021	776	1,22,95,000	21,10,000
2022	1167	2,75,25,000	15,25,000
2023	616	68,20,000	शून्य
कुल	2801	5,78,60,000	65,22,500

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

यमुना को साफ करने के लिए हो रहे उपायों की वजह से यमुना के प्रदूषण में कमी के दावे किए जा रहे हैं। यमुना के एक हिस्से में पिछले दिनों नाव चलाने का भी ट्रायल हुआ। इसके बावजूद यमुना किनारे मलबा डालने वालों की संख्या में कमी नहीं आई है। अहम यह है कि मलबा डालने वालों के चालान तो किए जाते हैं, लेकिन इसकी वसूली नहीं हो पा रही है।

डीपीसीसी की अप्रैल 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में 30 अप्रैल तक यमुना में मलबा डालने के डीडीए ने 616 चालान किए। लेकिन इनमें से एक भी वसूली नहीं हो सकी। यह 616 चालान करीब 68,20,000 रुपये के हुए हैं। वहीं, 2023 के शुरुआती चार महीनों में ही चालान की संख्या काफी अधिक हो गई है। 2021 में पूरे साल 776, 2019 में 186 और 2020 में 54 चालान हुए थे। 2020 कोरोना से सबसे बुरी तरह प्रभावित रहा था और उस साल लॉकडाउन की वजह से इंडस्ट्री और निर्माण कार्य पर रोक रही थी।

रिपोर्ट के अनुसार, 2018 से अप्रैल 2023 तक यमुना में मलबा डालने, अवैध पार्किंग करने और कूड़ा डालने के लिए कुल 2801 चालान किए गए। यह चालान 5,78,60,000 रुपये के हुए हैं। इनमें से महज 65,22,500 रुपये की वसूली हो चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार, आईएल एंड एफएस ने यमुना बाढ़ क्षेत्र से कुल 50,860 मीट्रिक टन मलबा उठाया है। वहीं, डीडीए ने यमुना किनारे मलबा डालने के चालान किए हैं।

डीडीए के अफसरों को कॉल कर खुद को बताया एलजी, केस दर्ज

■ एनबीटी न्यूज, नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने डीडीए सतर्कता विभाग कि एक शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन दोनों अधिकारियों को एक शख्स वॉट्सऐप कॉल कर खुद को दिल्ली का एलजी वीके सक्सेना बता रहा था। पुलिस अधिकारी के मुताबिक 25 मई को यह एफआईआर दर्ज की गई थी। डीडीए के सतर्कता विभाग के मुताबिक दिए गए शिकायत में बताया गया था कि 23 मई को वॉट्सऐप कॉल पर उसके दो अधिकारियों से संपर्क किया था।

सतर्कता विभाग के दो अधिकारियों को पहले एक अज्ञात नंबर से वॉट्सऐप कॉल आया और कॉल करने वाले ने खुद को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना बताया। लेकिन उन्होंने फोन काट दिया। फिर उसने उन्हें मेसेज भी भेजा कि मैं दिल्ली का एलजी वीके सक्सेना हूं। उसने अपने डीपी पर भी एलजी का फोटो लगा रखा था। हालांकि उन्होंने कॉलर से बात नहीं की। इसलिए यह पता नहीं चल सका है कि कॉलर का फोन करने का मुख्य उद्देश्य क्या था।

बरुआ क्लब की बड़ी जीत

डीडीए चिल्ला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित दो दिवसीय ग्रासरूट स्कूल अंडर-10 फुटबॉल टूर्नामेंट में छह टीमों ने भाग लिया। पहले दिन के मुकाबलों में बरुआ ए टीम ने कॉसमॉस क्लब को 1-0 से, वहीं चिल्ला बरुआ बी टीम ने यूनाइटेड टीम को 1-0 से हराया। तीसरे मैच में यूनाइटेड ने टाइगर क्लब पर 1-0 से जीत हासिल की। दिन के आखिरी मैच

हिन्दुस्तान
नई दिल्ली
गुरुवार
29 जून 2023

'18 माह में कूड़े के पहाड़ साफ करेंगे'

दावा

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बुधवार को पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा दिल्ली मास्टर प्लान 2041 पर आयोजित एक संवादात्मक सत्र में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगले 18 माह में दिल्ली के तीनों कूड़े के पहाड़ों को साफ कर दिया जाएगा।

उपराज्यपाल (एलजी) ने कहा कि 57 किलोमीटर में फैले नजफगढ़ नाले को भी जल्द साफ कर दिया जाएगा।

57 किलोमीटर लंबे नजफगढ़ ड्रेन खंड में से 30 किलोमीटर को साफ कर दिया गया है और बाकी को अगले कुछ महीनों में साफ कर दिया जाएगा। वहीं, इस कार्यक्रम में डीडीए के उपाध्यक्ष सुभाशीष पांडा भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पहले की तरह इस साल दिल्ली के हजारों निवासियों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर साफ नजफगढ़ नाले के किनारे 8 स्थानों पर योग किया।

'यमुना का खोया हुआ गौरव वापस लाना है'

भावुक होकर उपराज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए यमुना नदी का खोया हुआ गौरव वापस लाना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इस प्रयास में सिग्नेचर ब्रिज से आईटीओ बैराज तक यमुना के 11 किलोमीटर के हिस्से को साफ किया गया है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
THURSDAY, JUNE 29, 2023

DATED

Heaping Shame: These Wetlands Are Becoming New Homes For Inert Waste

Flattening Of Landfills At Expense Of Waterbodies Where Dumping Is Taking Place At Night

Kushagra.Dixit@timesgroup.com

New Delhi: While not a single wetland has been notified in the city since the implementation of the Wetlands (Conservation and Management Rules), 2017, three years ago, several waterbodies are ironically being filled up with inert waste from municipal landfills. Sites in north Delhi, which are historically part of the Yamuna catchment area, are being packed with the dark material, with local residents telling **TOI** that the dumping is done at night.

TIMES VIEW: Wetlands bring down pollution levels, raise groundwater tables, and in general help improve a city's ecosystem. It is, therefore, extremely worrying that they are being treated as dustbins in north Delhi. The government should take note of this worrying development and make sure that it stops at the earliest. There should also be urgency in notifying wetlands. Delhi cannot afford to lose whatever is left of its water bodies.

A large lake in Jaroda near the Bhalswa landfill has been almost levelled, but still has a part active aquatic ecosystem. Like this lake, there are several being compromised, which is ironic since government departments are mandated to rejuvenate over 1,045 wetlands listed two years ago. None of those wetlands has been legally vetted so far.

"A wetland should be preserved as far as possible. It has functions like recharging the water table and containing excess rainwater in its natural depression," said Ravi Agarwal, environmentalist from Toxics Link. "There is a natural flow towards waterbodies in low-lying areas and flooding results if they are levelled. We saw this in Chennai."

Ecologists associated with the city's wetland-related projects cautioned not only that filling up the lakes would expose the surrounding areas to flooding, but also that filling them with waste material without scientific analysis would pollute the soil and groundwater with heavy metals, pathogens and microplastics.

Commenting on the use of inert waste from the sanitary landfills whose garbage mountains are being reduced, Agarwal expressed apprehension that this could introduce toxic elements in the soil and groundwater. "Disposing of the waste has to be done after proper scientific study and consultation, not casually like this," he said.

Ecologists also pointed out that this was exactly how the landfills at Bhalswa and Okhla were created. Bhalswa was once called Horseshoe Lake for its shape. "Those wetlands had been covered over in a matter of a few days," revealed a government official. "Levelling the wetlands instead of rejuvenating them is stupidity."

TOI reached out to officials in Delhi government, Delhi Pollution Control Committee and the landowning agency Delhi Development Authority on the matter, but there was no reply from them. The Municipal Corporation of Delhi, which operates the landfills, did respond and said, "No garbage is being dumped, rather inert and construction and demolition waste segregated from bio-mining of legacy waste at Bhalswa landfill are being dumped to level the low-lying area on the request of DDA. These low-lying areas are not designated wetlands or water bodies. The material is being dumped after proper testing of ingredients and the test report said the material was safe for filling/levelling of vacant and low-lying areas."

"These bodies are wetlands, let there be no doubt," declared a government official. "For a wetland, the sub-sediment has to be saturated which means even in dry state if you dig up, the soil would be wet. In these places, surface water is clearly visible and there is a presence of microphytes with grass species like *Phragmites australis, Phragmite karka. Typha latifolia, Typha angustifolia* and Paspalum which grow in wetlands are also present in these places. Several water birds such as Indian moorhen, little grebe, spot billed ducks too are seen here." said the official requesting anonymity.

However, Delhi Wetland Authority lists only two wetlands in Jharoda Majra within the Yamuna Biodiversity Park and none in Gopalpur. Despite natural indicators like riverine grass, wet sub-sediment, etc, which qualify them as wetlands, many sites in the region remain unlisted as waterbodies.

Photos: Tarun Rawat

WHAT A WASTE!

- Wetlands/ponds are being filled with waste procured from landfill sites
- Officials say the wetlands being levelled are not listed or recognised
- The wetlands being filled with waste have riverine grasses and water, and are home to aquatic birds
- Garbage from landfill also being used to create embankment at places

WHY IT'S A WORRY

- Recognised or not, wetlands or ponds in low-lying areas, such as Wazirbad and Jharoda, protect the areas from flooding
- During the monsoon, they recharge the groundwater
- If filled with waste, groundwater is contaminated with micro-plastic, heavy metals and pathogens
- Have an adverse impact on health

CITY OF LAKES?

- The Centre in **2020** issued guidelines on Wetland (Conservation and Management) Rules, 2017, to legally protect waterbodies
- Wetlands that are over two hectares must be notified
- In **August 2021**, the Delhi government prepared a list of 1,045 wetlands for notification or legal protection

10 wetlands prioritised —not a single one notified yet

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---- दैनिक जागरण नई दिल्ली, 29 जून, 2023 DATED----------

आवासीय योजना के लिए कल से पंजीकरण

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : डीडीए 30 जून से अपनी आवासीय योजना का चौथा चरण शुरू करने जा रहा है। इसमें कुल 5,540 फ्लैटों की नीलामी की जाएगी। डीडीए की वेबसाइट पर दोपहर 12 बजे से 'पहले आओ, पहले पाओ' योजना का पंजीकरण शुरू हो जाएगा। डीडीए की योजना है कि लोगों को 10 जुलाई तक फ्लैटों के पंजीकरण और बुकिंग शुल्क जमा कराने का समय दिया जाए। इस अवधि तक उन्हें फ्लैटों का बुकिंग शुल्क जमा कराने का समय मिलेगा। वहीं, डीडीए की तरफ से बुकिंग करा रहे आवेदकों के नाम-पता समेत अन्य जानकारियों की ट्रैकिंग भी सुनिश्चित की जाएगी।

डीडीए के एक अधिकारी ने बताया कि 10 जुलाई के बाद फ्लैटों की बुकिंग

10 जुलाई तक कर सकेंगे 'पहले आओ, पहले पाओ' योजना के तहत आवेदन

कराने वालों को लगभग पांच दिन के लिए फ्लैटों की जगहों पर जाने का समय मिलेगा। इससे लोग अपनी प्राथमिकता के अनुसार चयन करने वाला फ्लैट देख सकेंगे। इसके लिए डीडीए लोगों को अपने इंजीनियर, अधिकारी का नंबर भी उपलब्ध कराएगा। साथ ही डीडीए की योजना है कि आनलाइन पोर्टल पर फ्लैटों की बुकिंग करने वालों को उनकी ई-मेल आइडी पर सीधे तय समय, डीडीए के इंजीनियर, अधिकारी का नंबर उपलब्ध करा दिया जाए। वहीं, डीडीए की वेबसाइट पर भी इस संबंध में सभी प्रकार की जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी।

डीडीए के अधिकारी ने बताया है कि 30 जून 12 बजे के बाद जिस भी समय लोगों की तरफ से फ्लैटों का पंजीकरण करने के बाद बुकिंग शुल्क जमा कराया जाएगा, उसके कुछ ही घंटों में आवेदकों को फ्लैटों का डिमांड कम अलाटमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा।

झुग्गी-झोपड़ी पर कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने झुग्गी-झोंपड़ी खाली करने से जुड़े डीडीए के आदेश पर रोक लगा दी है। आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति तारा विस्तारा गंजू की पीठ ने डीडीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि मामले में परीक्षण करने की जरूरत है, ऐसे में अगली सुनवाई तक झुग्गी-झोंपड़ी को खाली करने व ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगाई जाती है। मामले में अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। याचिकाकर्ता निरंजन कंदर ने याचिका दायर कर कहा कि डीडीए ने उन्हें उनका पक्ष रखने का मौका दिए बिना जगह खाली करने का आदेश जारी किया है। (जासं)

परियोजनाएं शुरू करने से पहले निकायों से लें मंजूरी : पीडब्ल्यूडी

राज्य, नई दिल्ली : पीडब्ल्यूडी ने अधिकारियों को भूमि कब्जे की प्रक्रिया पूरी होने और स्थानीय निकाय की मंजूरी लेने के बाद ही परियोजनाएं आवंटित करने का निर्देश दिया है। 27 जून को जारी एक कार्यालय ज्ञापन में विभाग ने कहा कि इससे उन विवादों से बचने में मदद मिलेगी, जिनके कारण परियोजनाओं में देरी होती है। विभाग ने कहा है कि यह देखा गया है कि बाधा-मुक्त भूमि की उपलब्धता और स्थानीय निकाय की मंजूरी सुनिश्चित किए बिना काम दिया जाता है। इसके कारण ठेकेदारों के साथ विवाद उत्पन्न होते हैं जिसके परिणामस्वरूप जटिलताएं होती हैं। विभाग ने कहा है कि कभी-कभी, साइट/भूमि की अनुपलब्धता और एमसीडी, दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, डीडीए, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति जैसे निकायों की मंजूरी न मिलने से काम शुरू हुए बिना ही अनुबंधों को रद करना पड़ता है। ज्ञापन में सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल-2022 में एक प्रविधान का हवाला दिया गया है, जो एनआइटी के अनुमोदन से पहले आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------- नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । गुरुवार, 29 जून 2023

फिर लुभाने लगी भलस्वा झील की खूबसूरती

परिवार के साथ बोटिंग के लिए बड़ी संख्या में पहुंचते हैं लोग

■ राजेश पोहार, भलस्वा झील

दिल्ली की भलस्वा झील एक बार फिर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनने लगी है। गर्मी की छुट्टियों के बीच दिल्ली के लोग रोज यहां बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। दिल्ली टूरिज्म की ओर से झील में बोटिंग की सुविधा दी गई है, जिनमें पैडल बोट के अलावा मोटरबोटिंग की भी सुविधा है। यहां अधिकतर लोग परिवार और बच्चों को लेकर पहुंचते हैं।

झील के रखरखाव का काम डीडीए कर रहा है

दिल्ली टूरिज्म ने भलस्वा झील में बोटिंग की सुविधा भी शुरू की है

हालांकि भलस्वा लैंडफिल साइट की तरफ से अभी भी झील की सफाई का काम काफी बचा हुआ है। जिस कारण भलस्वा कॉलोनी के इर्द-गिर्द काफी अधिक गंदगी दिखाई देती है। इसमें भलस्वा गांव से निकलने वाले नालों का पानी भी मिल रहा है। हालांकि जिस जगह से बोटिंग होती है, वहां बेहद साफ-सफाई कर दी गई है। इसके वजह से लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित हो रहा है। दिल्ली टूरिज्म के एक अधिकारी ने बताया कि झील के रखरखाव की जिम्मेदारी डीडीए की है। यह करीब 34 हैक्टेयर क्षेत्र में फैली एक प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। इसका पानी पहले के मुकाबले अब काफी साफ है। डीडीए इसकी साफ सफाई पर काम तेजी से काम कर रहा है। पहले इसकी हालत बहुत खराब थी। इसके बाद इसके जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया गया। इसे लेकर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच बयानबाजी भी देखने को मिली थी। लेकिन अभी फिलहाल गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए बड़ी संख्या में लोग अपने बच्चों के साथ यहां पहुंचते हैं और जमकर एंजॉय कर रहे हैं।

कल लॉन्च होगी DDA की स्कीम, 5540 फ्लैट्स होंगे

■ विस, नई दिल्ली : 30 जून को लॉन्च हो रही डीडीए की हाउसिंग स्कीम के लिए लोग 10 जुलाई तक अप्लाई कर सकेंगे। स्कीम में कुल 5540 फ्लैट होंगे। 30 जून को दोपहर 12 बजे से इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। डीडीए से मिली जानकारी के अनुसार, 10 जुलाई तक लोग रजिस्ट्रेशन और बुकिंग फीस जमा कर सकेंगे।

30 जून को दोपहर 12 बजे से इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे

10 जुलाई के बाद फ्लैटों की बुकिंग कराने वाले लोगों को करीब पांच दिन के लिए फ्लैटों की जगहों पर जाने का समय मिलेगा। इससे लोग अपनी पसंद के अनुसार फ्लैट का चयन कर सकेंगे। डीडीए लोगों को अपने इंजीनियर, अधिकारी का नंबर भी उपलब्ध कराएगा ताकि आवेदक लोगों से बात करके अपनी प्राथमिकता वाले फ्लैटों की लोकेशन पर जाकर उसे देख सकें और फ्लैटों का बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। बुकिंग करवाने वालों को उनकी ई-मेल आइडी पर सीधे निर्धारित समय, डीडीए के इंजीनियर, अधिकारी का नंबर उपलब्ध करा दिया जाए। वहीं, डीडीए की वेबसाइट पर भी इस संबंध में सभी तरह की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

डीडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी बताया कि बुकिंग फीस जमा कराने वालों को डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर कुछ ही घंटों में जारी कर दिए जाएंगे।

बिना गाइडलाइंस के रखे गए हिरण

इनब्रीडिंग बनी सबसे बड़ी समस्या, मिली थी मिनी जू की मान्यता

■ राम त्रिपाठी, नई दिल्ली

डियर पार्क के सभी 650 से अधिक हिरण एक ही वंश से हैं। किसी भी जंगल या चिड़ियाघर से समय-समय पर डियर नहीं लाए गए थे। दरअसल, उनका आपस में प्रजनन (इनब्रीडिंग) हो रहा है। डियरों की देखरेख करने वाला 'एनिमल ट्रेंड स्टाफ' भी नहीं है। साथ ही एक भी वेटरनरी डॉक्टर तक नहीं है। ऐसे में डियर पार्क में बड़ी संख्या में हिरण बीमार हो रहे हैं। कई तो जैविक बीमारियों से पीड़ित हैं। यही वजह है कि सेंट्रल जूलॉजिकल अथॉरिटी (सीजेडए) अब सभी हिरणों को वहां से हटाकर जंगल भेजने को मजबूर है। हालांकि वन्य क्षेत्र में भेजने का समय अभी तय नहीं है।

देश में हिरण व अन्य वन्यजीवों के रखरखाव व खानपान के लिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन) की गाइडलाइंस का हर चिड़ियाघर और सफारी को पालन करना पड़ता है, लेकिन डियर पार्क में इन गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है।

- सभी 650 से अधिक हिरण एक ही वंश से हैं
- न ट्रेंड स्टाफ न ही वेटनरी डॉक्टर है यहां पर

सीजेडए के मेंबर सेक्रेटरी डॉ. संजय कुमार शुक्ला ने बताया कि डियर पार्क को जिस उद्देश्य से मिनी जू की मान्यता दी गई थी उसे वो पूरा नहीं कर पाया है। पार्क का मैनेजमेंट देख रही डीडीए ने दूसरी नस्ल के डियर भी नहीं लाए हैं। ताकि इनब्रीडिंग न हो। इसके अलावा रिवेल्यूशन रिपोर्ट भी नहीं दी गई है।

तेजी से बढ़ते हैं जेनेटिक रोग : सीजेडए के एक दूसरे अधिकारी ने बताया कि इनब्रीडिंग सबसे बड़ी समस्या है। इससे अनुवांशिक रोग तेजी से बढ़ते हैं।

पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (यूपी) के पीएचडी स्कॉलर ममता मिश्र और नारायण यादव ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इनब्रीडिंग से पैदा होने वाले वन्य जीवों का शरीर कमजोर होता है। वजन कम होता है। रोग से लड़ने की क्षमता न के बराबर रह जाती है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

हिन्दुस्तान
नई दिल्ली
गुरुवार
29 जून 2023

पहले आओ, पहले पाओ आवासीय योजना का चौथा चरण, पिछली बार कम खरीद को देखते हुए इस बार नई योजना बनाई

पांच हजार फ्लैटों के लिए कल से बुकिंग

डीडीए की आवासीय योजना

■ राहुल मानव

नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की तरफ से पहले आओ, पहले पाओ आवासीय योजना का चौथा चरण 30 जून यानी कल लॉन्च होगा। इसमें डीडीए की तरफ से कुल 5,540 फ्लैटों के लिए लोगों को बुकिंग कराने का अवसर मिलेगा।

इसके तहत जसोला में 40 हाई इनकम ग्रुप (एचआईजी), द्वारका और नरेला में 200 मिडिल इनकम ग्रुप (एमआईजी) फ्लैटों के लिए पंजीकरण होगा। वहीं, नरेला में 900 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) फ्लैटों के साथ लोकनायक पुरम, रोहिणी, सिरसपुर और नरेला में कुल 4400 लो इनकम ग्रुप (एलआईजी) आवासों के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का अवसर मिलेगा।

डीडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि योजना के तहत ईडब्ल्यूएस और एलआईजी को ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। छूट की दरों के साथ फ्लैटों की कीमतें निर्धारित की गई हैं। ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के लिए रजिस्ट्रेशन और बुकिंग करने वाले आवेदनकर्ताओं को 10 लाख रुपये से कम पूरे परिवार का आय प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।

सिरसपुर, रोहिणी और नरेला में नहीं हुई बिक्री : उत्तर पश्चिमी दिल्ली के सिरसपुर, नरेला और रोहिणी सेक्टर-34 व 35 में डीडीए ने पहले भी कई बार आवासीय योजना के तहत फ्लैट की योजना लॉन्च की थी। हालांकि, इन सभी जगहों पर लोगों ने कनेक्टिविटी और नौकरियों के बेहतर संसाधन व सुरक्षा व्यवस्था के कारणों के अभाव की वजह से फ्लैट नहीं खरीदे।

उत्तर पश्चिमी दिल्ली में डीयू के दो बड़े कॉलेज अदिति महाविद्यालय बवाना और स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज अलीपुर में स्थित है, जो नरेला के रूट पर आता है। साथ ही अलीपुर से आगे एनआईआईटी भी स्थित है।

डीयू का अदिति महाविद्यालय रिठाला मेट्रो स्टेशन से 29 किमी दूर है और स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज 24 किमी दूर है। दोनों कॉलेजों के छात्रों का कहना है कि बवाना और नरेला में रहने वाले छात्रों, स्थानीय लोगों के लिए नरेला व बवाना मेट्रो की कनेक्टिविटी रिठाला मेट्रो स्टेशन के साथ जोड़ना बेहद जरूरी है, तभी डीडीए की आवासीय योजना को और भी ज्यादा बल मिलेगा।

लोगों को देखने के लिए पांच दिन मिलेंगे : डीडीए के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, बुकिंग कराने वाले लोगों को 10 जुलाई के बाद पांच दिन के लिए फ्लैटों की जगहों पर जाने के लिए समय मिलेगा, जिससे लोग अपनी प्राथमिकता के अनुसार चयन करने वाले फ्लैट को देखने जा सकेंगे। इसके लिए डीडीए अपने इंजीनियर और अधिकारी का नंबर भी उपलब्ध कराएगा, ताकि लोग आसानी से फ्लैटों का बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें।

स्पोर्ट्स और इंटीग्रेटेड फ्लैट कॉम्प्लेक्स का निर्माण : डीडीए के मुताबिक, रिठाला मेट्रो स्टेशन से नरेला व बवाना इलाकों में मेट्रो के परिचालन के लिए डीएमआरसी की तरफ से कार्य सुनिश्चित किए जा रहे हैं। इससे लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। वहीं, नरेला के सेक्टर-ए7 में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और इंटीग्रेटेड फ्लैट कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है। सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस को नरेला में 10 अलग-अलग जगहों पर पुलिस स्टेशन बनाने के लिए जमीन आवंटित की गई है। नरेला में भी बेहतर सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित की गई है।

5,540
फ्लैटों के लिए 30 जून दोपहर 12 बजे से आवेदन करें

■ ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी के लिए पंजीकरण का मौका

इतनी है कीमत

₹2.08-2.18 करोड़ कीमत है जसोला विहार के एचआईजी फ्लैटों की	₹1.25-1.35 करोड़ कीमत है द्वारका के एमआईजी फ्लैटों की
₹ 01 करोड़ कीमत है नरेला के एमआईजी फ्लैटों की	₹15 लाख कीमत है नरेला और रोहिणी में एलआईजी की
₹17 लाख कीमत है सिरसपुर में एलआईजी फ्लैटों की	
₹ 10-13 लाख कीमत है नरेला के ईडब्ल्यूएस फ्लैटों की	₹ 30 लाख कीमत है लोक नायक पुरम में एलआईजी की

200 एमआईजी फ्लैट हैं नरेला और द्वारका में
40 एचआईजी फ्लैट हैं जसोला में
900 ईडब्ल्यूएस फ्लैट नरेला में हैं

एलआईजी फ्लैट हैं लोकनायक पुरम, रोहिणी, सिरसपुर और नरेला में

इतना शुल्क देकर बुकिंग होगी

■ ईडब्ल्यूएस के लिए 50 हजार रुपये
■ एलआईजी के लिए एक लाख रुपये
■ एमआईजी फ्लैट के लिए चार लाख
■ एचआईजी के लिए दस लाख रुपये

तीन माह में शुल्क जमा करना होगा

■ आवेदन के बाद तीन माह तक फ्लैट का पूरा शुल्क जमा कराने का समय मिलेगा। इसमें जितना बुकिंग शुल्क जमा कराया गया है, उसके बाद शेष रकम जमा करानी होगी।
■ पहले दो माह में बिना किसी ब्याज के आवेदकों को फ्लैट की कीमत चुकाने का अवसर दिया जाएगा।
■ तीसरे माह में आवेदकों को 11 फीसदी ब्याज के साथ कीमत चुकानी होगी। बुकिंग रद्द कराते हैं तो उन्हें पंजीकरण शुल्क वापस नहीं मिलेगा।
■ यदि तीन माह में कुल कीमत जमा नहीं होती है तो उसका पैसा डीडीए फ्रीज कर लेगा और वापस नहीं मिलेगा।

10 जुलाई तक मौका

डीडीए के अनुसार, 30 जून को दोपहर 12 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया जाएगा। 10 जुलाई तक पंजीकरण और बुकिंग शुल्क जमा कराने का समय मिलेगा। इसके बाद डीडीए आवेदक के नाम-पते समय अन्य जानकारी हासिल करेगा, ताकि पता चल सके कि आवेदक ने जानकारी सही भरी है या नहीं।

आवेदन की प्रक्रिया

आवासों की बुकिंग के लिए **www.dda.gov.in** पर जाएं। यहां पहले आओ, पहले पाओ लिंक के जरिए रजिस्ट्रेशन करें। इसमें आधार कार्ड, फोटो, ई-मेल आईडी, फोन नंबर समेत अन्य जानकारी देनी होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए कुल 1,180 रुपये शुल्क लिया जाएगा। इसके बाद फ्लैट बुकिंग के लिए विंडो खुलेगी। फ्लैट का चयन करने के बाद वह वेबसाइट में मौजूद विंडो में लाल रंग के निशान के साथ नजर आएगा, जिसके तहत डीडीए द्वारा अगले 15 मिनट के लिए उस फ्लैट को ब्लॉक कर दिया जाएगा, ताकि कोई अन्य आवेदक उसका चयन न कर सके। बुकिंग शुल्क जमा कराने के लिए लोगों को 15 मिनट का समय मिलेगा। बुकिंग के पास ई-मेल या फोन नंबर पर आवेदक को सूचना दी जाएगी। वहीं, बुकिंग शुल्क जमा कराने के बाद 12 घंटे में डिमांड लेटर कम अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा।

पहले तीन चरण में 60 फीसदी ही बिके

■ डीडीए की ओर से सितंबर 2022 में पहले आओ, पहले पाओ की आवासीय योजना को तीन चरणों में मार्च 2023 तक शुरू किया गया था।
■ इसमें दिल्ली में करीब चार हजार ईडब्ल्यूएस और एलआईजी की योजना को शुरू किया गया। इनमें 2800 ईडब्ल्यूएस और 1200 एलआईजी फ्लैट थे।
■ सितंबर, 2022 से मार्च 2023 तक 2000 ईडब्ल्यूएस और 400 एलआईजी फ्लैट बिके।

योजना के तहत कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है

■ डीडीए की पहले आओ, पहले पाओ आवासीय योजना में यह नियम लागू नहीं है कि अगर दिल्ली में किसी आवेदक का पहले से 67 मीटर (करीब 80 गज) का मकान है, वो 30 जून को शुरू होने वाली योजना में फ्लैट बुक नहीं करा सकता है।
■ एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी फ्लैटों को कोई भी बुक करा सकता है। इसमें कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। डीडीए की यह योजना घोषणा करने बाद तब तक जारी रहेगी, जब तक इससे संबंधित अन्य कोई फैसला डीडीए द्वारा जारी नहीं किया जाता है।
■ दिल्ली में किसी के पास एक या कई मकान या जमीन है तो वह अपनी इच्छा के अनुसार कितने भी फ्लैटों की बुकिंग करा सकता है। इसमें कोई बाध्यीकरण डीडीए द्वारा नहीं लगाया जाएगा।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------- DATED

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
FRIDAY, JUNE 30, 2023

Pollution in VK: DPCC submits report to NGT

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: A joint committee led by the Delhi Pollution Control Committee (DPCC) has submitted a report to the National Green Tribunal (NGT) regarding dumping of construction and demolition waste, causing pollution in the Vasant Kunj area.

The residents of Vasant Kunj's E block had last year approached the NGT with several complaints related to dumping of waste, breaking of footpaths and waterlogging.

The DPCC had said that the DDA had been directed to conduct a meeting with the residents to resolve the matter. A meeting was held in April, during which it was found that some issues were unresolved.

In March, the NGT has issued an order after RWA members of Sector E, Pocket-2, had raised concerns of health hazards because of stagnant water in open drains on the northern side of the DDA Legal Housing Complex wall.

The DDA submitted its reply in March, saying it had "repaired/constructed footpath and also removed all C&D waste from road/sweeping... as recommended by the DPCC".

On waterlogging, the DPCC report said that the DDA had floated a tender for construction of a wall to prevent seepage of dirty water at a cost of Rs 36 lakh.

Registration for 5,500 flats starts today

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: The Delhi Development Authority (DDA) is all set to begin the registrations for 5,500 flats from 12 pm on June 30 under its Phase IV Housing Scheme.

The flats are located in Jasola (having 40 High Income Group or HIG flats), Dwarka (having 50 Middle Income Group or MIG flats), Lok Nayak Puram, Rohini, Siraspur and Narela. In Narela, there are 149 MIG flats in addition to Low Income Group (LIG) and Economic Weaker Section (EWS) flats.

The registration fee will be Rs 1,000 irrespective of the kind of flat buyers are applying for. The fee is non-refundable.

Then, a window of 4-5 days will be given to buyers to visit the sample flats at each site and do a booking of their choice of flat. An online portal will also be launched for the purpose of booking the flats online.

Rain relief for T3: DDA to complete phase I of drain near Dwarka in July

Vibha.Sharma@timesgroup.com

New Delhi: Delhi Development Authority (DDA) will complete the work on phase I of a new drainage system near Sector 8 in Dwarka for discharge of rainwater by July 31, which is likely to address the problem of flooding at Terminal 3 of IGI Airport and surrounding areas during heavy monsoon rain.

The long-awaited project will also bring respite for some sectors in Dwarka. The length is 2.8km, out of which 1.4km is being completed in the first phase while phase II is likely to be ready by December end, said DDA officials.

File photo

A DDA official said the drain was being constructed along the boundary wall of the airport opposite Sector 8 and would be linked to the upstream and downstream sides of trunk drain 2

During an interactive session with industrialists, lieutenant governor VK Saxena said the project was conceived in 2019 and the work started in August 2020. "It was getting stuck due to a delay in tree cutting permission from the forest department. However, after long efforts, the permission was granted and till date 95% work has been completed on phase I. We are expecting that no issue of waterlogging will be reported this monsoon in and around the area," said Saxena.

A DDA official said the drain was being constructed along the boundary wall of the airport opposite Sector 8 and would be linked to the upstream and downstream sides of trunk drain 2. "We have completed the majority of work on the upstream side. A patch of 200 metres is pending where work for constructing the raft and sidewall is left. The site is located at a traffic intersection and the work got delayed due to waterlogging during the recent rain. We are sure to complete the work by July end," said the official. The first phase drain is 20 metres wide and 2 metres deep.

"While the previous drain wasn't big enough to meet the requirements, we ensured that the size of both new drains would be enough to ensure no water collection happened at the northern side of the airport," said an official. A study was carried out to solve the problem after the airport authority approached DDA, he added. "On the southern side, Public Works Department has already constructed a drain."

DDA had moved the forest department for cutting trees in November 2020, but didn't receive any nod for a long time, said officials. On the LG's direction, DDA moved Delhi High Court seeking a direction to the department for granting the permission and managed to get a favourable judgment. The permission was finally granted on August 1, 2022.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

Hindustan Times
NEW DELHI
FRIDAY, JUNE 30, 2023

Put up for sale

Over 5,600 flats across six areas — Jasola, Dwarka, Narela, Lok Nayak Puram, Rohini and Siraspur — are up for sale under DDA's new housing scheme

Locality	Unit type	No. of units	Size (in sqm)	Approx cost
Jasola	3BHK	41	162-177	₹2.1-2.2 crore
Dwarka	2BHK	50	120	₹1.2-1.3 crore
Narela	1BHK	3,400	30-35	₹10-20 lakh
	2BHK	150	150	₹1 crore
Lok Nayak Puram	1BHK	140	40	₹27-28 lakh
Rohini	1BHK	1,700	33	₹14 lakh
Siraspur	1BHK	125	35	₹17 lakh

How to apply

- Log in to the DDA website www.dda.gov.in
- Open the scheme page and register
- Fill personal details and choice of flat
- Pay registration amount (as per unit type)
- Flat will be booked and demand letter will be sent to applicant on contact details provided
- Make rest of the payment within three months

Online portal to open at 5pm

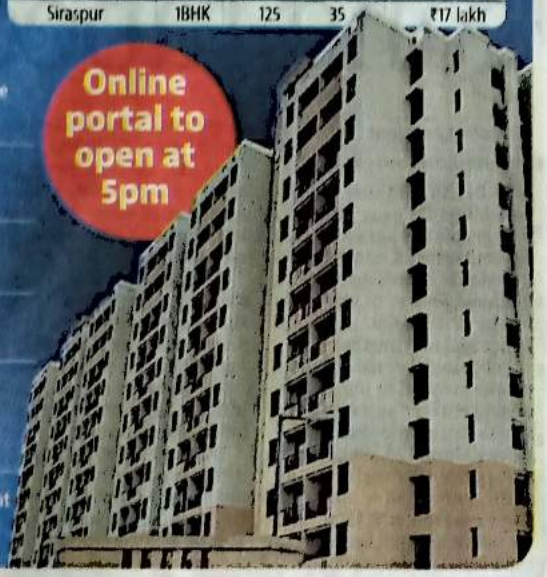

DDA's scheme for 5,600 flats to be launched today

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Delhi Development Authority (DDA) will launch its housing scheme from Friday wherein around 5,600 flats across six locations in Delhi will be sold off.

The scheme will be open to the public at 5pm and allotment will be done on a "first-come, first-serve" basis.

The fourth phase of DDA's housing scheme will include houses in the LIG (lower income group), MIG (middle income group) and HIG (higher income group) categories across south-east Delhi's Jasola, southwest Delhi's Dwarka, west Delhi's Lok Nayak Puram, and northwest Delhi's Narela, Rohini and Siraspur.

Officials said that all allotments will be done through online applications, for which applicants need to log on to the DDA website, fill details and register to book their flats.

The registration amounts vary as per category of flats. For the LIG category, the registration amount is ₹10,000 plus 18% GST for those who are in the economically weaker section (EWS) category and ₹1 lakh plus GST for those in the normal LIG category. For MIG flats, the booking amount is Rs ₹4 lakh plus GST, and for HIG, it is ₹10 lakh plus GST.

"Since these flats are on a 'first-come, first-serve' basis, they are allotted to those who submit registration amounts. Once the process is done, a demand letter will be generated and sent to the allottee, and they will have to pay the remainder amount within three months," said a DDA official.

During registration, one may need to upload an identity proof, an address proof (not necessarily of Delhi) and an EWS certificate for those applying in this category.

Jasola is the only area where HIG flats are being offered. There are 41 such 3 BHK flats for sale. Dwarka has 50 2 BHK flats for sale while there are 1,700 1 BHK flats up for grabs in Rohini. While Siraspur has 125 1 BHK flats for the auction, Lok Nayak Puram has 140 1 BHK flats.

On the other hand, Narela has 3,400 1 BHK flats and another 150 2 BHK flats for sale.

Officials said that DDA has an unsold inventory of about 13,000 flats, of which around 5,600 are being put up for sale from Friday.

However, more flats may soon be added to the scheme, while another lot of flats may be up for sale during Navratri festive season in October.

"We undertook a survey and various efforts were made to increase sale of these flats, like reducing prices, introducing the 'first-come, first-serve" scheme instead of the draw of lots, and relaxing application norms. Efforts are also being made to improve connectivity in these areas," said a DDA official.

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शुक्रवार, 30 जून 2023

कुरैनी: पार्क में हरियाली नहीं, असामाजिक तत्वों का जमघट

■ एनबीटी न्यूज, कुरैनी: नरेला नई अनाज मंडी के सामने कुरैनी गांव का डीडीए का पार्क बदहाल हालत में है। पार्क की बाउंड्रीवॉल जगह-जगह से टूटी हुई है। पार्क में आए लोगों का कहना है कि शाम में यहां असामाजिक तत्वों का जमघट लग जाता है। पार्क में मेंटिनेंस की कमी की वजह से हरियाली गायब हो रही है। पार्क में धूल-मिट्टी उड़ती रहती है। चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। आरोप है कि पार्क की देखरेख के लिए लोगों ने डीडीए से शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई लोगों की मांग है कि पार्क की बाउंड्रीवॉल ठीक कराई जाए, यहां पौधे और घास लगाई जाए, लाइट्स और बैठने के लिए बेंच का भी इंतजाम किया जाए।

DDA के 5,500 फ्लैट्स की बुकिंग आज से

■ प्रेस, नई दिल्ली: डीडीए अपनी हाउसिंग स्कीम 'पहले आओ पहले पाओ' के तहत 5,500 फ्लैट्स ला रहा है। अगर दिल्ली में किसी के पास 67 वर्ग मीटर या इससे छोटा घर है तो वह भी इस स्कीम में अप्लाई कर सकता है। इन फ्लैट्स के लिए 30 जून यानी आज दोपहर 12 बजे से बुकिंग शुरू होगी। स्कीम में HIG, 3BHK के 40 फ्लैट जसौला में, 200 MIG फ्लैट्स द्वारका और नरेला में, LIG के 4500 फ्लैट्स लोकनायक पुरम, रोहिणी, सिरसपुर और नरेला में हैं। वहीं, EWS कैटिगरी के भी 900 फ्लैट्स नरेला में हैं। इस स्कीम में 10 जुलाई तक बुकिंग करने वालों को 5 दिन के लिए फ्लैट्स देखने का मौका भी मिलेगा। ▸▸पेज 3

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------- हिन्दुस्तान
नई दिल्ली
शुक्रवार
30 जून 2023

डीडीए फ्लैट के नाम पर युवती को ठगा

ट्रांस हिंडन। इंदिरापुरम में जालसाजों ने फ्लैट का ऑनलाइन पंजीकरण करने के बहाने युवती से 25 हजार रुपये ठग लिए। इंदिरापुरम थाने में साइबर ठगी का मुकदमा दर्ज कराया गया है।

निहो स्कॉटिस सोसाइटी निवासी सिल्की जैन ने बताया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की वेबसाइट पर फ्लैटबुक करने के लिए इंटरनेट पर सर्च किया था। उन्होंने साइट खोलकर कर सारी जानकारी भर दी। इसके बाद 25 हजार की राशि भरने के लिए कहा गया। वेबसाइट पर दिए गए खाते में 25 हजार रुपये की धनराशि भी जमा करा दी। बाद में पता चला कि वेबसाइट और खाता संख्या दोनों फर्जी है। जालसाजों ने डीडीए से मिलती जुलती ही वेबसाइट बना रखी थी। एसीपी इंदिरापुरम स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि युवती की शिकायत के बाद साइबर सेल मामले की जांच कर रही है।

डीडीए की वेबसाइट पर आवासीय योजना आज लॉन्च होगी

नई दिल्ली, व.सं.। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की तरफ से पहले आओ,पहले पाओ आवासीय योजना के चौथे चरण की शुरुआत आज होने जा रही है। इसमें कुल 5,540 फ्लैटों के लिए बुकिंग कराने का अवसर मिलेगा।

इसमें जसोला में 40 एचआईजी (हाई इनकम ग्रुप), द्वारका और नरेला में 200 एमआईजी (मिडिल इनकम ग्रुप), नरेला में 900 ईडब्ल्यूएस फ्लैट के साथ लोक नायक पुरम, रोहिणी, सिरसपुर और नरेला में कुल 4400 एलआईजी (लो इनकम ग्रुप) फ्लैट के लिए पंजीकरण का अवसर मिलेगा। फ्लैटों की बुकिंग के लिए डीडीए की वेबसाइट www.dda.gov.in पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं।

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शुक्रवार, 30 जून 2023

शाहबाद डेयरी : पार्क में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप

पुलिस ने तीन नाबालिग समेत पांच पकड़े, एक आरोपी अभी फरार

■ एनबीटी न्यूज, शाहबाद डेयरी

इलाके में एक पार्क में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना के वक्त नाबालिग पार्क में अपने दोस्त के साथ बैठी थी। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।

पुलिस ने पीड़ित लड़की के बयान पर केस दर्ज कर तीन नाबालिग समेत पांच को पकड़ लिया है। आरोपियों की पहचान राहुल उर्फ छोटू (19) और बॉबी (20) के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

पुलिस के मुताबिक, नाबालिग लड़की अपने दोस्त के साथ 27 जून की रात पार्क में बैठी हुई थी। तभी वहां तीन नाबालिग समेत पांच लड़के आए। इनमें से एक नाबालिग व राहुल उर्फ छोटू (19) और बॉबी ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों को देखकर लड़की का दोस्त मौके से फरार हो गया। इधर पीड़ित लड़की ने घर आकर परिवार वालों को आपबीती बताई। परिवार ने इसकी शिकायत पुलिस से की। शाहबाद डेयरी थाना पुलिस ने केस दर्ज कर राहुल और बॉबी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ही शाहबाद डेयरी के रहने वाले हैं। आरोपियों से पूछताछ करने पर पुलिस ने एक आरोपी नाबालिग को पकड़ा।

पूछताछ में पता चला कि घटना के दौरान दो नाबालिग वहां खड़े होकर वारदात देख रहे थे। पुलिस ने इन दोनों को भी पकड़ लिया है। पुलिस के मुताबिक घटना में एक आरोपी सागर फरार है। जिसकी पुलिस तलाश कर रही है।

पीड़िता का दोस्त वहां से भाग गया

पुलिस के अनुसार, पीड़िता परिवार के साथ शाहबाद डेयरी में रहती है। पिता मजदूर हैं। पीड़िता की पड़ोस में रहने वाले लड़के से दोस्ती थी। लड़के ने पीड़िता से शादी करने का वादा किया था। घटना वाले दिन दोनों जहां बैठे थे, वह डीडीए की जमीन है। पीड़िता दोस्त के साथ बैठकर बातचीत कर रही थी। इसी बीच वहां से गुजर रहे आरोपियों ने उन्हें देखा। आरोपियों ने पीड़िता के दोस्त को धमकाया। वह वहां से भाग गया। नाबालिग, राहुल और बॉबी ने गैंगरेप किया। पीड़िता ने आरोपियों से छोड़ने की गुहार लगाई। लेकिन आरोपियों ने एक नहीं सुनी।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शुक्रवार, 30 जून 2023

पहली बार 'पहले आओ-पहले पाओ' आधार पर मिलेंगे एचआईजी और एमआईजी फ्लैट्स

DDA लाया फ्लैट्स ही फ्लैट्स, आज से करें अप्लाई

- यदि दिल्ली में किसी के पास 67 स्क्वायर मीटर या इससे छोटा घर है तो वह इस स्कीम में अप्लाई कर सकता है
- स्कीम तब तक जारी रहेगी जब तक डीडीए की तरफ से इसे लेकर कोई निर्णय नहीं होता। डिमांड के अनुसार फ्लैट बाद में भी जोड़े जा सकते हैं

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

घर लेने का सपना देख रहे हैं तो डीडीए की पहले आओ-पहले पाओ के तहत आ रही हाउसिंग स्कीम में आज से अप्लाई कर सकते हैं। स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यदि आपके पास दिल्ली में छोटा घर या फ्लैट है तो भी आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही एचआईजी और एमआईजी सेगमेंट के फ्लैट्स पहली बार पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर बुक किए जा रहे हैं।

डीडीए इस स्कीम में करीब 5500 फ्लैट्स ला रहा है। यह फ्लैट्स 30 जून को दोपहर 12 बजे से बुक किए जा सकते हैं। स्कीम में एचआईजी 3 बीएचके के 40 फ्लैट जसोला में हैं। इसके अलावा द्वारका और नरेला में 200 फ्लैट्स एमआईजी के हैं। स्कीम में सबसे अधिक एलआईजी के फ्लैट्स शामिल हैं। इस कैटिगरी के करीब 4500 फ्लैट्स हैं। यह फ्लैट्स लोकनायक पुरम, रोहिणी, सिरसपुर और नरेला में हैं। साथ ही स्कीम में ईडब्ल्यूएस कैटिगरी के 900 के करीब फ्लैट्स नरेला में हैं। ईडब्ल्यूएस कैटिगरी में फ्लैट बुक करवाने वाले लोगों को अपनी फैमिली इनकम 10 लाख पर ईयर से कम का सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा।

डीडीए के अनुसार, 10 जुलाई तक बुकिंग करवाने वालों को पांच दिन के लिए फ्लैट्स देखने का मौका भी मिलेगा। इसके लिए उन्हें समय और दिन की जानकारी ईमेल से दी जाएगी। ईमेल में उन्हें संबंधित इंजीनियर और अधिकारी के नंबर भी दिए जाएंगे। यह अधिकारी लोगों को उनका बुक करवाया फ्लैट दिखा देंगे। डीडीए ने इस स्कीम में सभी पुराने फ्लैट्स को शामिल किया है। जसोला और द्वारका में बने फ्लैट्स की लोकेशन अच्छी है। वहीं सिरसपुर, रोहिणी और नरेला में बने फ्लैट्स डीडीए पहले भी कई स्कीम में उतार चुका है।

क्या प्लस पॉइंट

- द्वारका के फ्लैट्स दो से तीन साल पहले ही तैयार हुए हैं। द्वारका में काफी साल के बाद डीडीए ने नए फ्लैट्स बनाए हैं
- एलआईजी में भी फ्लैट्स का साइज अच्छा है
- यहां पर कुछ पेड पार्किंग का भी स्पेस है, जिन्हें लोग बाद में खरीद सकते हैं

क्या माइनस पॉइंट

- डीडीए के एचआईजी और एमआईजी के फ्लैट्स मौजूदा सोसायटी फ्लैट्स से महंगे लग रहे हैं
- द्वारका के एमआईजी फ्लैट्स नाले के पास बने हैं। ऐसे में कई फ्लैट्स की खिड़कियां नालों की तरफ खुलती हैं
- सिरसपुर में बने फ्लैट्स छोटे हैं
- नरेला, सिरसपुर आदि के आसपास बुनियादी सुविधाओं का अभाव है

NBT LENS
समझिए खबरों के अंदर की बात

DDA ने क्यों बदला फ्लैट बेचने का तरीका

पहली बार डीडीए ने एचआईजी और एमआईजी फ्लैटों को पहले आओ, पहले पाओ की तर्ज पर बेचना शुरू किया है। इससे पहले डीडीए स्कीम लॉन्च करके पहले लोगों से फॉर्म भरवाता था और फिर ड्रॉ के जरिए फ्लैट अलॉट होते थे। लेकिन बीते एक दशक से डीडीए को प्राइवेट बिल्डर्स से जबरदस्त टक्कर मिल रही है। इसकी वजह से उसकी स्कीम लगातार फ्लॉप हो रही थी। इसी वजह से डीडीए ने अपना तरीका बदला। पिछले साल डीडीए ने जब इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट्स बेचे तो उसके आधे से अधिक फ्लैट्स बिक गए। अब उसने एमआईजी और एचआईजी फ्लैट्स के खरीददारों को लुभाने के लिए ये स्कीम लॉन्च की है।

कितना होगा बुकिंग अमाउंट

EWS	LIG	MIG	HIG
50 हजार	एक लाख	चार लाख	दस लाख

ऐसे होगी DDA फ्लैट्स की बुकिंग

- फ्लैट्स की बुकिंग के लिए सबसे पहले डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट www.dda.gov.in पर जाएं
- यहां 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर स्कीम का लिंक मिलेगा। इसे क्लिक करें
- इसके बाद मांगी गई जानकारी भरते हुए फ्लैट बुकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करें। इसमें आपको अपनी आधार कार्ड, फोटो, ईमेल आईडी, फोन नंबर आदि जानकारियां भरनी होंगी
- रजिस्ट्रेशन के लिए जीएसटी समेत करीब 1180 रुपये ऑनलाइन पे करने होंगे।
- इसके बाद फ्लैट बुकिंग के लिए विंडो खुलेगी। इसमें कैटिगरी के हिसाब से ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी के फ्लैट्स का चयन करना होगा
- अपनी पसंद के फ्लैट पर क्लिक करते ही उसका कलर चेंज हो जाएगा। इसके बाद 15 मिनट तक उस फ्लैट को कोई और चूज नहीं कर पाएगा।

- इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद पेमेंट गेटवे खुलेगा। इसके तहत अलग-अलग कैटिगरी के लिए निर्धारित बुकिंग फीस जमा करवानी होगी
- यदि पंद्रह मिनट के दौरान फ्लैट की बुकिंग फीस जमा नहीं होती तो इसके बाद उक्त फ्लैट एक बार फिर लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगा और उसका चयन वह कर पाएंगे।

बाकी रकम से जुड़ी बातें

- बुकिंग के बाद तीन महीनों में फ्लैट की पूरी कीमत जमा करवानी होगी, इसमें बुकिंग फीस भी शामिल रहेगी
- पहले दो महीने में यदि फ्लैट की कीमत चुकाते हैं तो कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा
- इसके बाद यदि तीसरे महीने में कीमत चुकाई जाती है तो उसपर 11 प्रतिशत ब्याज लगेगा।
- बुकिंग कैंसिल करने पर रजिस्ट्रेशन फीस वापस नहीं होगी
- यदि तीन महीने में फ्लैट की पूरी कीमत जमा नहीं होती तो आवेदक का पैसा डीडीए फ्रीज कर लेगा और यह वापस नहीं मिलेगा
- 'पहले आओ, पहले पाओ' की पिछली स्कीमों को मिले रिस्पॉन्स
- सितंबर 2022 में यह स्कीम पहली बार शुरू हुई, यह स्कीम तीन चरणों में मार्च 2023 तक चली।
- इस स्कीम में करीब चार हजार ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट्स शामिल किए गए
- इस दौरान इनमें से करीब 2400 फ्लैट्स बिके

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शुक्रवार, 30 जून 2023

500 कोचिंग सेंटरों की लिस्ट, नियम तोड़ने वाले होंगे सील

मुखर्जी नगर कोचिंग सेंटर में आग की घटना के बाद हो रहा सर्वे

Sudama.Yadav@timesgrop.com

File Photo

मास्टर प्लान में कोचिंग इंस्टीट्यूट की कैटिगरी कमर्शल बताई गई है

■ मुखर्जी नगर कोचिंग सेंटर में आग की घटना के बाद एमसीडी कोचिंग सेंटरों की लिस्ट तैयार कर प्रत्येक जोन में सर्वे कर रही है। अब तक 500 से अधिक कोचिंग सेंटर्स का सर्वे कर उनकी लिस्ट तैयार की गई है। 3 जुलाई को लिस्ट हाई कोर्ट की डबल बेंच को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद जिन कोचिंग सेंटरों में यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज (यूबीबीएल-2016) नियमों का उल्लंघन हो रहा है, उन्हें सील किया जाएगा।

3 जुलाई को कोचिंग सेंटर्स की इस लिस्ट को हाई कोर्ट की डबल बेंच के सामने पेश किया जाएगा

कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एमसीडी अफसर मास्टर प्लान-2021 खंगाल रहे हैं। एमसीडी अफसरों का कहना है कि यह हैरान करने वाली बात है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने आप में एक इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन यह इंस्टीट्यूशनल एरिया में नहीं खोले जा सकते हैं। कोचिंग सेंटर सिर्फ कमर्शल या मिक्स्ड लैंड यूज (एमएलयू) एरिया में ही खोले जा सकते हैं। कोचिंग सेंटर इंडस्ट्रियल एरिया में खोलने के लिए भी कोई मनाही नहीं है। मिक्स्ड लैंड यूज एरिया में कोचिंग सेंटर खोलने की मुख्य शर्त यह है कि रोड की चौड़ाई कम से कम 18 मीटर होनी चाहिए। अफसरों का कहना है कि मास्टर प्लान में कोचिंग इंस्टीट्यूट की कैटिगरी कमर्शल बताई गई है, जिसके चलते ही यह सारी समस्या पैदा हुई है। मास्टर प्लान में कोचिंग इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर या वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के फायर सेफ्टी नियमों के बारे में कोई नियम नहीं है। जिसके चलते फायर डिपार्टमेंट भी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेता है। इसके चलते ही मुखर्जी नगर कोचिंग सेंटर में आग के बाद कुछ ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्ट्रचरल सेफ्टी के बारे में भी मास्टर प्लान में कोई पुख्ता प्लान नहीं है। अफसरों का कहना है कि वैसे तो मास्टर प्लान के अनुसार ही दिल्ली में सभी चीजों को नियंत्रित करने की हिदायत दी जाती है, लेकिन मास्टर प्लान खंगालने पर उसमें चीजों को नियंत्रित करने का कोई पुख्ता प्लान ही नहीं मिलता।

क्या बोले एक्सपर्ट

डीडीए के पूर्व प्लानिंग कमिश्नर और शहरी विकास मंत्रालय के एक समिति के सदस्य रहे एके जैन के अनुसार कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले बच्चों की सेफ्टी के लिए पुख्ता नियम – कायदे बनाने की जरूरत है। सबसे पहले कोचिंग सेंटर के लिए फायर सेफ्टी नियमों का उल्लेख मास्टर प्लान में होना चाहिए। मास्टर प्लान – 2021 में कोचिंग सेंटर के लिए फायर के प्रावधानों का उल्लेख ही नहीं है। कोचिंग सेंटर के लिए स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट भी मैंडेटरी होनी चाहिए, लेकिन इसका भी मास्टर प्लान में उल्लेख नहीं है। कोचिंग सेंटर इंस्टीट्यूशनल कैटिगरी में नहीं रखे गए हैं।

मुफ्त की सुविधाओं वाले बयान पर दी प्रतिक्रिया

एलजी के बयान पर CM ने जताया विरोध

■ विस, नई दिल्ली : दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली वालों को दी जाने वाली मुफ्त सुविधाओं के बारे में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के एक बयान पर सरकार और आम आदमी पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई है। बुधवार को पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से दिल्ली के नए मास्टर प्लान-2041 पर चर्चा करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। डीडीए के चेयरमैन और दिल्ली के एलजी वी. के. सक्सेना भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यहां उन्होंने दिल्ली सरकार की तरफ से दी जाने वाली मुफ्त की सुविधाओं की तरफ इशारा करते हुए एक बयान में कहा कि 'दिल्ली को अब मुफ्त की चीजों (सुविधाओं) की आदत पड़ गई है।'

एलजी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि दिल्ली के लोगों को मुफ्त की सुविधाओं की पड़ चुकी है आदत

एलजी के बयान पर सीएम ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए गुरुवार को एक ट्वीट कर कहा, 'दिल्ली के लोग मेहनतकश हैं। कड़ी मेहनत से उन्होंने दिल्ली को संवारा है। एलजी साहब, आप बाहर से आए हैं। आप दिल्ली और दिल्लीवालों को नहीं समझते। इस तरह दिल्ली के लोगों का अपमान मत कीजिए। दिल्ली सरकार दूसरी सरकारों की तरह चोरी नहीं करती। पैसे बचाकर लोगों को सहूलियत देती है। इससे आपको क्यों परेशानी है?' आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक और दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने भी एलजी से कहा, 'अगर ईमानदारी से काम करके दिल्ली सरकार कुछ सुविधाएं दिल्लीवालों को दे रही है, तो आपको उसमें क्या दिक्कत है? आपको और अन्य नेताओं को भी तो ये सारी सुविधाएं मिलती हैं।'